भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

21.09.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1664 का उत्तर

उत्पादन यूनिटों का निगमीकरण

1664. श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सभी रेल नेटवर्कों में रेलगाड़ी सेवाओं के निजीकरण की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी उत्पादन यूनिटों का निगमीकरण किया जा रहा है अथवा उन्हें एकल निकाय के रूप में गठित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): रेल मंत्रालय ने यात्रियों को विश्वस्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से कुछ चुनिंदा मार्गों पर निवेश करने और आधुनिक रेक शामिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पहल के भाग के रूप में, रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से डिज़ाइन, निर्माण, वित्त और परिचालन (डीबीएफओ) के आधार पर, लगभग 109 आरंभिक-गंतव्य जोड़ियों (12 कलस्टर में विभाजित) की यात्री गाड़ियां चलाने के लिए 1 जुलाई, 2020 को 12 अर्हता अनुरोध (आरएफक्यू) जारी किए हैं। ये मार्ग समूचे भारतीय रेल नेटवर्क में फैले हुए हैं और इनकी सूची सार्वजनिक डोमेन अर्थात http://www.indianrailways.gov.in/IndicativeRoutesfor12clusters.pdf में उपलब्ध हैं। गाड़ी परिचालन और संरक्षा प्रमाणन का उत्तरदायित्व भारतीय रेल के पास ही रहेगा।

(ग) और (घ): भारतीय रेल की उत्पादन इकाइयों के पूंजीकरण का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

******

Sk